आज के बजट में राजस्थान में खुलेगा ''सौगातों का पिटारा''

वित्त मंत्री दीया कुमारी पेश करेंगी, भजनलाल सरकार का तीसरा बजट

जयपुर, 10 फरवरी। केन्द्र सरकार के बजट के बाद अब राजस्थान की जनता की निगाहें राज्य सरकार के बजट पर टिकी हैं। भजनलाल शर्मा सरकार का तीसरा वार्षिक बजट वित्तीय वर्ष 2026-27, बुधवार सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा। बजट को राज्य की वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी प्रस्तुत करेंगी। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री कार्यालय में बजट को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

- सरकार की ओर से पहले ही संकेत दिए जा चुके हैं कि यह बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों व बुनियादी ढांचे को केन्द्र में रखकर तैयार किया गया है।
- माना जा रहा है कि बजट में नई योजनाओं, भर्तियों और विकास कार्यों की बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं।

सरकार की ओर से पहले ही संकेत दिए जा चुके हैं कि यह बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों और बुनियादी ढांचे को केन्द्र में रखकर तैयार किया गया है। प्रदेशवासियों में इस बजट को लेकर खासा उत्साह है, क्योंकि माना जा रहा है कि इसमें नई योजनाओं, भर्तियों और विकास कार्यों की बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बजट सरकार के कार्यकाल का मध्य बजट है, इसलिए इसमें की गई घोषणाओं के अमल में आने की संभावना भी अधिक रहती है।

राज्य बजट 2026-27 को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात उप मुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मंगलवार शाम मुख्यमंत्री कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव (वित्त) वैभव गालरिया, शासन सचिव वित्त (व्यय) टीना सोनी, शासन सचिव वित्त (बजट) राजन विशाल, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कुमारपाल गौतम एवं निदेशक वित्त (बजट) बृजेश किशोर शर्मा उपस्थित थे।

रोजगार को लेकर सरकार इस बार बड़ा कदम उठा सकती है। लगभग डेढ़ लाख नई सरकारी भर्तियों की घोषणा की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में इजाफा भी किया जा सकता है। किसानों के लिए सम्मान निधि बढ़ाने, ब्याज मुक्त फसली कर्ज योजना का दायरा बढ़ाने और फसलों की सरकारी खरीद को लेकर अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है।

इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी सरकार का फोकस साफ नजर आ रहा है। कई शहरों में रिंग रोड और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में जर्जर सरकारी स्कूलों की मरम्मत, नए मेडिकल कॉलेज खोलने और डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती पर भी सरकार का ध्यान रहने की संभावना है। कुल मिलाकर यह बजट प्रदेश के विकास की दिशा तय करने वाला और आने वाले वर्षों की नीति को मजबूत करने वाला माना जा रहा है।

राजस्थान बजट 2026-27 को लेकर यह माना जा रहा है कि सरकार रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी और बड़ी संख्या में नई भर्तियों का रास्ता साफ हो सकता है। इसके साथ ही, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बजट का हिस्सा बन सकती हैं।

'परीक्षा परिणाम में देरी के कारण चयन से वंचित नहीं किया जा सकता'

जयपुर, 10 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर भर्ती-2020 से जुड़े मामले में कहा है कि विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा परिणाम और अंक तालिका देरी से जारी करने के आधार पर पात्र अभ्यर्थी को चयन से वंचित नहीं किया जा सकता।

- हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड की अपील खारिज की।

अदालत ने इस मामले में एकलपीठ के आदेश को सही माना व कर्मचारी चयन बोर्ड की अपील को खारिज कर दिया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर गत 2 फरवरी का अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले से जुड़े अधिवक्ता एमएफ बेग ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने सार्वजनिक निर्माण विभाग में जूनियर सिविल इंजीनियर के 276 पदों पर साल 2020 में भर्ती निकाली थी। भर्ती विज्ञापन में शर्त थी कि अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में इंजीनियरिंग या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। वहीं संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते परीक्षा से पहले वे योग्यता पूरी कर लें। एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे लोकेश कुमार ने भर्ती परीक्षा में शामिल होकर मेरिट में स्थान प्राप्त किया, लेकिन उसके यह कहते हुए नियुक्ति नहीं दी गई कि उसका परिणाम बाद में घोषित हुआ है। लोकेश कुमार ने इसे चुनौती दी और एकलपीठ ने उसे नियुक्ति देने का आदेश दिया था।

'शिक्षित और समझदार लोग राजनीति में आएं व जनसेवा को प्राथमिकता दें'

सचिन पायलट ने स्व. राजेश पायलट की 80वीं जयन्ती पर निःशुल्क दिव्यांग सामग्री वितरण शिविर का उद्घाटन किया

टोंक, 11 फरवरी (निसं)। किसान नेता, पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 80वीं जयंती के अवसर पर, जिला कांग्रेस कमेटी व श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सहयोग से मुख्यालय स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित निःशुल्क दिव्यांग सामग्री वितरण शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि हम सभी के मन में यह भाव रहता है कि गरीब, असहाय लोगों की मदद किस प्रकार से की जाये, परन्तु कई बार यह भावना मूर्त रूप नहीं ले पाती। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, जो इस भावना को साकार रूप प्रदान करते है, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति ऐसी ही एक संस्था है, जिसने अनेकों अक्षम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है।

- उन्होंने कहा, राजेश पायलट ने अपने जीवन में ऐसी छाप छोड़ी कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति मेहनत और लगन से बहुत ऊचाईयां हासिल कर सकता है।
- सचिन पायलट ने कहा कि भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति ने अनेकों अक्षम लोगों को अपन पैरों पर खड़ा कर मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है।

पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. राजेश पायलट की 80वीं जयंती पर टोंक में निःशुल्क दिव्यांग सामग्री वितरण शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांजनों को कृत्रिम हाथ-पैर, श्रवण यंत्र, बैसाखी, व्हीलचेयर एवं वॉकर वितरण किये।

कार्यक्रम में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक पद्म भूषण डॉ. डी.आर. मेहता सहित अनेक विशिष्टजन उपस्थित थे। इस अवसर पर राजेश पायलट को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पायलट ने अपने जीवन में ऐसी छाप छोड़ी है कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति, जिसके पास कुछ न हो, वह भी अपनी मेहनत और लगन से बहुत ऊँचाइयां हासिल कर सकता है। एक पुरानी कहावत है, 'जिस पेड़ की जड़ें गहरी नहीं होतीं, वह ऊंचा नहीं उठ सकता'। उनकी सोच थी कि शिक्षित एवं समझदार लोग राजनीति में आगे आयें और जनसेवा को प्राथमिकता दें। मुझे खुशी है कि राजेश पायलट जी की जयंती पर आज हम इस शिविर के माध्यम से कुछ लोगों की मदद कर पाये हैं।

उल्लेखनीय है कि तीन दिवसीय शिविर में दिव्यांजनों को कृत्रिम हाथ-पैर, श्रवण यंत्र, बैसाखी, व्हीलचेयर एवं वॉकर आदि का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भी राजेश पायलट के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर रामविलास चौधरी, पूर्व विधायक कमल बैरवा, देहात ब्लॉक अध्यक्ष कैलाशी देवी मीणा, सैयद महमूद शाह, अल्पसंख्यक विभाग जिला अध्यक्ष बरकत हसीन, सेवादल जिला अध्यक्ष अब्दुल खालिक फोजू, राम मीणा, केदार चौधरी, देवकरण गुर्जर, रामदेव गुर्जर, रामलाल संडीला, मंडल अध्यक्ष इमरान पहलवान के अलावा, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे।

'जब तक ''अविश्वास ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर यह पद किसी सहयोगी दल को दिया जाता है, लेकिन भाजपा के पास भारी बहुमत होने के कारण उसने उपाध्यक्ष नियुक्त करना उचित नहीं समझा।

अब सदन की कार्यवाही स्पीकर पैनल को चलानी होगी।

सदन 13 फरवरी को एक महीने के लिए स्थगित हो जाएगा और बजट पारित करने के लिए मार्च में फिर से बैठक होगी। राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन वे कल दोपहर 12 बजे बजट पर बोलेंगे।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ओम बिड़ला के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखने और निष्पक्ष व्यवहार करने के बजाय, सत्तारूढ़ पार्टी के निर्देशों पर और उनके अनुसार कार्य किया।

पहले भी तीन बार लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन वे हमेशा खारिज हो गए। पहला प्रस्ताव 1954 में अध्यक्ष मालवीय के खिलाफ लाया गया था।

'नरवणे की किताब बिक्री के लिए उपलब्ध है'

राहुल गांधी ने नरवणे की 15 जनवरी 2023 की एक्स पोस्ट को शेयर करके यह दावा किया।

नई दिल्ली, 10 फ़रवरी। लोकसभा में जारी गतिरोध के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की कथित किताब ''फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी'' के प्रकाशक पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को दावा किया कि किताब बिक्री के लिए उपलब्ध है।

राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपने मोबाइल में जनरल नरवणे का 15 दिसंबर 2023 का पोस्ट दिखाया। उन्होंने कहा कि यह जनरल नरवणे का एक्स पोस्ट है, जिसमें उन्होंने लिखा था, नमस्ते दोस्तो, मेरी किताब अब उपलब्ध है। बस इस लिंक का अनुसरण करें। आनंदपूर्वक पढ़ें। जय हिंद।

राहुल ने कहा, सवाल यह है कि या तो जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर पैनग्विन प्रकाशन, लेकिन मुझे पूर्व सेनाध्यक्ष पर भरोसा है, वे झूठ नहीं बोलेंगे।

- उक्त पोस्ट में नरवणे ने किताब उपलब्ध होने का दावा किया था। पोस्ट में पेनग्विन इंडिया के एक्स पोस्ट का स्क्रीन शॉट भी लगाया था जिसमें किताब उपलब्ध होने की बात कही थी।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जनरल नरवणे ने किताब में जो बातें लिखी हैं, वे सरकार और प्रधानमंत्री के लिए असहज हैं और इसी वजह से इस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है।

राहुल गांधी ने जिस पोस्ट का जिक्र किया था, उसे जनरल नरवणे ने 15 दिसम्बर 2023 को एक्स पर साझा किया था। इसमें उन्होंने पैनग्विन इंडिया के एक एक्स पोस्ट का स्क्रीनशॉट लगाया था।

उसमें पैनग्विन प्रकाशन ने ई-कॉमर्स साइट अमेजन का लिंक साझा करते हुए लिखा था, चूँकि हम विजयदिवस की तैयारी कर रहे हैं। आइए, अपने देश के नायकों का सम्मान करें। शुरुआत करते हैं मनोज नरवणे से, जो भारत के 28वें थलसेनाध्यक्ष रहे और दशकों तक देश के लिए लड़े। उनकी कहानी जानने के लिए अभी फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, प्री ऑर्डर करें।

भारत को बांग्लादेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के साथ भेदभाव न हो। लेकिन अब उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया से लगभग बाहर कर दिया गया है।

विडंबना यह है कि छात्र आंदोलन का एक छोटा हिस्सा अब जमात के साथ मिलकर नई सरकार में प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि देश कट्टरपंथी दिशा में ही आगे बढ़ सकता है। बांग्लादेश की संभावित राजनीतिक स्थिति और नई सरकार का चरित्र निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना रहेगा। इससे भारत के पूर्वी हिस्सों में अस्थिरता बढ़ सकती है और नई सरकार में हिंदुओं पर अत्याचार जारी रहने की आशंका है।

यह जरूरी हो जाता है कि भारत बांग्लादेश के मामले में अधिक सक्रिय नीति अपनाए, क्योंकि दुनिया के कई बड़े देश अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रणनीतिक और राष्ट्रीय हितों के अनुसार नीतियां बना रहे हैं।

ममता बनर्जी को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खुद ही मामला रखने का फैसला किया। उनके वकीलों के पैनल में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे प्रसिद्ध वकील और सुप्रीम कोर्ट के कई अन्य वरिष्ठ वकील शामिल थे।

उन्होंने ऊंची आवाज में आरोप लगाया कि लोग रो रहे हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने रवीन्द्रनाथ टैगोर का हवाला दिया। उन्हें लगा कि इस महान हस्ती का उल्लेख करने से उनकी मांग मान ली जाएगी।

उन्होंने अदालत में खुद अपनी बात रखने के दौरान तय समय से ज्यादा समय लिया और अपनी शिकायतों को विस्तार से बताया। उनका आरोप था कि चुनाव आयोग मामूली कारणों पर लोगों के नाम मनमाने तरीके से मतदाता सूची से हटा रहा है।

अदालत ने उनके आरोपों पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी।

अदालत ने फैसला दिया कि राज्य में, और जिन राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू की गई है, वहां प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के जारी रहने दिया जाए। अदालत के हस्तक्षेप के बाद ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ अभियान चलाती रही हैं।

कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गए। उन्होंने न केवल मर्यादा का उल्लंघन किया, बल्कि उस बेंच को भी पार कर दिया, जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सांसदों को नियंत्रित करना पड़ा, ताकि कोई झड़प न हो। राजग की महिला सांसद इस बर्ताव से बेहद नाराज हैं।

रिजिजू ने कहा कि भाजपा की महिला सांसदों ने कांग्रेस की महिला सांसदों के अनुचित व्यवहार को लेकर ओम बिड़ला को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

चुनाव से पहले युवाओं के खाते में 1500 रु. डालेंगी ममता बनर्जी

यह कैश ट्रांसफर अंतरिम बजट में घोषित ''युवसाथी'' योजना के तहत किया जाएगा।

कोलकाता, 10 फरवरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य सचिवालय नवान्न में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतरिम बजट में घोषित 'युवसाथी' योजना को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार यह योजना अब एक अप्रैल से लागू करेगी। इसके तहत, राज्य के 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 15 सौ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले यह योजना 15 अगस्त से शुरू करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन नया आर्थिक वर्ष एक अप्रैल से शुरू होता है, इसलिए उसी दिन से योजना लागू करने का फैसला किया गया है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस योजना का लाभ उन्हीं युवाओं को मिलेगा, जिन्होंने माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है और जो वर्तमान में बेरोजगार हैं। यह भत्ता अधिकतम पांच वर्षों तक दिया जाएगा। हालांकि, जैसे ही किसी लाभार्थी को नौकरी मिल जाएगी, उसी समय से भत्ता बंद हो जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो युवा किसी अन्य सरकारी भत्ता योजना का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। हालांकि, ऐक्यश्री, मेधाश्री या स्मार्ट कार्ड जैसी छात्रवृत्तियों का लाभ लेने वाले युवाओं को युवसाथी योजना से वंचित नहीं किया जाएगा।

- प.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में इस योजना के बारे में विस्तार से बताया।

मुख्यमंत्री ने आवेदन प्रक्रिया को लेकर बताया कि युवसाथी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समय की कमी और आवेदन की सही तरीके से जांच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रत्यक्ष आवेदन की व्यवस्था की है, ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति वंचित न रह जाए। इसके लिए राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर 15 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेंगे और रोज़ाना सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। छुट्टी के दिनों में शिविर बंद रहेंगे। आवेदन करने वाले सभी लोगों को रसीद दी जाएगी और बाद में इन आवेदनों को डिजिटाइज किया जाएगा।

शशि थरूर ने आम बजट पर चर्चा शुरू की

नई दिल्ली, 10 फ़रवरी। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में जारी गतिरोध समाप्त होने के बाद, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में आम बजट 2026 पर चर्चा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने सरकारी खर्च में कमी और कर राजस्व संग्रह में ठहराव की आलोचना की।

उन्होंने अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते पर भी सवाल उठाए और कहा कि भारत का व्यापार फायदा 45 अरब डॉलर है, लेकिन हमने यह डील कर ली कि अगले पांच साल में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान खरीदेंगे। यह निश्चित क्रय प्रतिबद्धता भारत के हित में नहीं है और दीर्घकाल में नुकसानदायक साबित होगी। उन्होंने कहा कि वाणिज्य और विदेश मंत्री को इस समझौते की टाइमलाइन और अन्य सवालों के जवाब देने चाहिए। ग़ालिब के एक मशहूर शेर का हवाला देते हुए थरूर ने कहा, ''हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, दिल के बहलाने के गालिब ये खयाल अच्छा है।

- इसी के साथ लोकसभा में गतिरोध समाप्त हो गया, थरूर ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर भी बात की।

दम्पति ने तीन बच्चों सहित आत्महत्या की

मरने वालों में मनीष उसकी पत्नी सीमा व 3 बच्चे हैं

मथुरा, 10 फरवरी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के महावन थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक परिवार के पांच सदस्यों के शव कमरे में मिले हैं। मरने वालों में पति-पत्नी और उनके तीन बच्चे हैं। सभी के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस को मिले सबूतों के आधार पर मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। मौके पर दीवार पर लिखा सुसाइड नोट और एक वीडियो भी मिला है।

पुलिस के अनुसार, महावन के ग्राम खप्परपुर में रहने वाला 35 वर्षीय मनीष खेती करता था। मंगलवार सुबह करीब दस बजे पुलिस को सूचना मिली कि मनीष, उसकी पत्नी सीमा (32), बेटी हनी (5), प्रियांशी (4) और बेटा पंकज (2) के शव घर के अंदर पड़े हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाया। पुलिस को मौके से दीवार पर लिखा सुसाइड नोट और कॉपी पर लिखा सुसाइड नोट मिला है। इसके अलावा मृतक मनीष का फोन भी मिला है, जिसमें सुसाइड को लेकर एक वीडियो भी बनाया गया था।

- दीवार पर लिखे एक नोट व एक वीडियो में आत्महत्या करने की बात कही गई है।

घर की दीवार पर लिखा है कि मैं मनीष आत्महत्या कर रहा हूं, किसी को परेशान न किया जाए। घर के कमरे में एक पर्ची मिली है, इस पर भी लिखा है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, किसी को परेशान न किया जाए। वीडियो में मनीष कह रहा है कि वह आत्महत्या कर रहा है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यह भी कहा है कि कुछ दिन पहले उन्होंने साढ़े 12 लाख रुपये की जमीन बेची थी, उसका पैसा भी उन्हें मिल गया है।

डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि मनीष की शादी को आठ साल बीत चुके हैं। उसके दो भाई हैं, जो गांव में ही अलग-अलग घरों में रहते हैं। मनीष अपने परिवार के साथ अलग रहता था। यह भी पता चला है कि कुछ दिनों से वह तंत्र-मंत्र के चक्कर में था। फिलहाल हर पहलू की जांच की जा रही है। यह आत्महत्या है, या फिर कोई और कारण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगा। परिवार और रिश्तेदारों से घटना के संबंध में जानकारी ली जा रही है।

असम में 2.43 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे

चुनाव आयोग ने असम में विशेष पुनरीक्षण की अंतिम वोटर लिस्ट जारी की

नई दिल्ली, 10 फरवरी। चुनाव आयोग ने मंगलवार को असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए विशेष पुनर्निरीक्षण (एसआर) 2026 की अंतिम मतदाता सूची जारी की है, जिसमें 2.49 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी असम के अनुसार, ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 2,52,01,624 थी, जो अंतिम सूची में घटकर 2,49,58,139 रह गई है, यानी ड्राफ्ट रोल से 2.43 लाख नाम हटाए गए। इस अंतिम सूची में 1,24,82,213 पुरुष मतदाता, 1,24,75,583 महिला मतदाता, और 343 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं।

- चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की स्पेशल इंडियन रोल की समय सीमा भी संशोधित कर दी है, अब इसका प्रकाशन 14 फरवरी को होगा।

असम के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया, विशेष पुनर्निरीक्षण (एसआर) 2026 के लिए इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 27 दिसंबर 2025 को पब्लिश की गई थी। इससे पहले 22 नवंबर 2025 से 20 दिसंबर 2025 तक हाउस-टू-हाउस सत्यापन अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया।

मतदाता अपनी दावे और आपत्तियां 27 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दाखिल कर सकते थे। चुनाव आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्पेशल रिविजन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि सटीक और अद्यतन मतदाता सूची सुनिश्चित की जा सके। यह सूची स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आधार है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के स्पेशल इंडियन रोल की समयसीमा भी संशोधित की है। अंतिम प्रकाशन अब 14 फरवरी 2026 को होगा। इसका कारण व्यापक मतदाता गणना और मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन बताया गया है। पश्चिम बंगाल में बूथ लेवल अधिकारी 11 दिसंबर 2025 तक घर-घर सत्यापन पूरा कर चुके थे। ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित हुई थी और दावे और आपत्तियां 15 जनवरी 2026 तक स्वीकार की गई थीं।

जयपुर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

देखे तो दोनो जापानी टूरिस्ट अंदर रुकने के कुछ ही देर बात बाहर जाते हुए दिखाई दिए।

आईसीसी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हुई, बल्कि वैश्विक क्रिकेट मंच पर पाकिस्तान की साख को एक और झटका लगा।

मैक्रों 17 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बयान के अनुसार, राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में संयुक्त रूप से भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन करेंगे। यह नवाचार वर्ष पूरे 2026 में भारत और फ्रांस दोनों देशों में मनाया जाएगा।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908